[श्री अश्विनी कुमार]

दूसरा जिला रांची जिसका लक्ष्य सब [illegible] ज्यादा 4.4 करोड़ था, वहां केवल [illegible] करोड़ बांटा गया।

तीसरा आदिवासी बहुल जिला गुमला, जिसका लक्ष्य 4.2 करोड़ था, वहां 1.2 करोड़ बांटा गया।

इसी प्रकार से नीचे की श्रेणी में आते-आते बोकारो के लिए 1.62 करोड़ का लक्ष्य था और केवल 37 लाख ही बांटा गया।

इसी प्रकार से महुआ जिले के अंदर भी 1.28 करोड़ का लक्ष्य था।

इसीलिए मैं आपके माध्यम से, आई0आर0डी0पी0 जो केंद्रीय योजना है, बैंकों का सबसे सीधा संबंध है, निवेदन करना चाहूंगा कि बैंकों को यह आग्रह किया जाए कि बिहार के अंदर वैसे ही बहुत बेरोजगारी है, दर-दर लोग भिखारी हैं, वहां के मजदूर सारे भारत के अंदर रोटी-रोजी के लिए भटकते हैं, और यह जो आई0आर0डी0पी0 उनके घर पर काम देने की योजना है, उसके अंदर भी केंद्र सरकार के बैंक जो चल रहे हैं उनके निर्देश में, उनका जो भी सहयोग है, वह इतना असहनीय है कि जिसके कारण बिहार की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि बिहार में रोजगार दिलवाने की योजना को जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा दिया है, उसका सम्पूर्ण उपयोग हो, इसकी ओर कृपया ध्यान दें।

Need to include Konkani Language in the Eighth Schedule of the Constitution

SHRI JOHN F. FERNANDES (GOA): Thank you, Madam Through my special mention I want to draw the attention of the Government and seek the support of this august House for inclusion of my State language. Konkani in the Eighth Schedule of the Constitution. Konkani is one of the oldest Indian languages. It is the first Indian language 1o possess printed books in India from 1556 onwards. This language to some extent was not encouraged and not allowed to be developed by our colonial rulers to avoid the spirit of nationalism. This language was recognised by the Sahitya Akademi in 1975 as one of the lteriary languages of India. Konkani is spoken and taught in schools and colleges in Goa, Karnataka, Kerala end other regions of K).ik?:n. In 1(106 this language was d::.'aved as the official language. It is a State language of the State of Goa. There are only two State languages in our country which are not included in the Eighth Schedule, one 's Manipuri and the second one is Konkani.

Madam, way back in 1990 we were very happy when the than Prime Minister, Mr. V. P. Singh announced that Konktni, Manipuri and Neptli will be included in the Eighth Schedule -of the Constitution. That was the 'only wise thing that he announced. But as of now we see there is no response from the Government.

Madam, by not including Konkani in the Eighth Schedule of the Constitution, we stand to lose a lot of benefits. By excluding Konkani, we don't get any facility from the programmes of National Book Trust and its subsidiary agencies. We don't get any facility from the programmes of NCERT. We don't get any facility from the DAVP and other publicity campaigns. We don't get any facility from the programmes of Film Division and ts agences, programmes of Directorate of Publicity, schemes of Departments of Educaton and Culture, etc. of Human Resource Development, from the programmes of neo-literates of the Government of India, programmes of national symposium of Poets on Akashvani and Doordarshan and other national meets of such type.

Madam, in one of the international conferences on languages, it was observed that Konkani is one of the non Constitutional languages of India. I feel this is a wrong message going to the international literat$_e$ community. I would, therefore, request the Government to see that Konkani along with other State languages, Manipuri and Nepali are included in the Eighth Schedule Of the Constitution. Thank you.

SHRI W. KULABIDHU SINGH (Manipur): Madam, Manipuri, Nepali and Konkani are the three official languages of three States of India which are not included in the Eighth Schedule of the Constitution. So I fully associate myself with my hon-friend.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Fernandes, you should have spoken in Konkani.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : Manipuri language also should be added in the Eighth Schedule of the Constitution.

SHRI JOHN F. FERNANDES (GOA): Please permit me. I will repeat it in Konkani.

THE DEPUTY CHAIRMAN; I hope it will be included in the Eighth Schedule. Then only you can speak. That was my reaction.

Export of Granite and marble stone from district Jalore in Rajasthan

श्री धूलेश्वर मीणा (राजस्थान) : महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं । आपके माध्यम से मैं उन उद्यमियों को जो राजस्थान में ग्रेनाइट के और मार्बल पत्थर के निर्यात से राजस्थान का और खास करके जालोर जिले का विश्व मानचित्र पर छाएगा, हार्दिक प्रशंसा करने खड़ा हुआ हूं जिसमें हमारे देश का और राजस्थान का खास करके जिले जालोर का बड़े गौरव की बात है । महोदया, उत्कृष्ट ग्रेनाइट पत्थर की उपलब्धता को देखते हुए राजस्थान शीघ्र ही विश्व मानचित्र पर अपना स्थान बना लेगा । राजस्थान में अभी तक किए गए सर्वेक्षण से 1200 मिलियन टन ग्रेनाइट के भंडार का पता लगाया गया है । यह सर्वेक्षण केवल 25 से 30 प्रतिशत क्षेत्र का ही किया गया है । जब शत-प्रतिशत क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाएगा तो वह कितने मिलियन टन ग्रेनाइट प्राप्त होगा यह आप और हम सब जान सकते हैं । इसी तरह से राजस्थान में मार्बल पत्थर के भी 4000 मिलियन टन और खनिज होने का पता लगा है । मार्बल सर्वेक्षण से हरे ढ़ंग का बहुत उत्कृष्ट मार्बल का पता चला है । जोधपुर में ग्रेनाइट व मार्बल व्यवसाइयों के कांफ्रेंस में आल इंडिया ग्रेनाइट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने यह जानकारी देते हुए कहा है, उन्होंने बताया है कि राजस्थान में ग्रेनाइट मार्बल व अन्य कीमती पत्थरों के भंडार का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण दल का गठन किया गया है । राजस्थान में ग्रेनाइट और मार्बल पत्थर की उपलब्धता के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से जोधपुर, जालोर और उदयपुर में अलग-अलग ग्रेनाइट उद्यमियों की कांफ्रेंस आयोजित की गई है । पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में ग्रेनाइट पत्थर उत्खनन का काफी कार्य हुआ है, जिसमें जालोर का ग्रेनाइट बहुत ही उत्कृष्ट सिद्ध हो रहा है । राजस्थान का मार्बल विश्व मार्केट में छाया हुआ है । अब यहां ग्रीन मार्बल के भंडार मिलने से बहुत बड़ी मात्रा में इस पत्थर का भी विदेशों में निर्यात की भारी संभावना बढ़ गई है । इसके अध्यक्ष श्री पोद्दार ने बताया है कि वर्ष 1995 तक इस देश के ग्रेनाइट मार्बल और पत्थर उद्योगों के क्षेत्र में 600 से ले करके 1000 करोड़ रुपये का निर्यात होने की संभावना हैं । उन्होंने यह भी बताया है कि वर्ष 1985 में 50 से 55 लाख रुपये का निर्यात हुआ जबकि इस वर्ष 350 करोड़ रुपये के निर्यात होने की संभावना है । निर्यात पर 10 प्रतिशत का कस्टम ड्यूटी लगने से ग्रेनाइट के धंधे को धक्का लगने की भी संभावना व्यक्त की गई हैं ।